**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1120

उत्‍तर देने की तारीख: 16 दिसम्‍बर, 2013

**महाराष्ट्र में मॉडल स्कूल**

1120. डा॰ भारतकुमार राऊतः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में छठीं से बारहवीं कक्षा तक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु उक्त ब्‍लॉकों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत ‘मॉडल स्कूल’ आरंभ किए जाने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से इन स्कूलों की इमारतों के निर्माण हेतु विहित 3.02 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है;

(ग) केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित अनुमान संबंधी प्रस्ताव के संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि जारी करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

(क) से (ग): जी, हां। राज्‍य सरकार ने 3.02 करोड़ प्रति स्‍कूल की निर्धारित इकाई लागत से अधिक अनुमानित निर्माण लागत से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्‍लॉकों (ई.बी.बी.) में 43 मॉडल स्‍कूलों की स्‍थापना का प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किया था। प्रस्‍ताव को इस मंत्रालय द्वारा इस शर्त पर अनुमोदित किया गया था कि या तो राज्‍य सरकार लागत अनुमान को संशोधित करके योजना के मानकों के भीतर लाए अथवा अपने स्‍वयं के संसाधनों से अतिरिक्‍त निधियां जुटाए।

(घ): राज्‍य सरकार द्वारा तत्‍पश्‍चात प्रस्‍तुत संशोधित योजना के आधार पर इस संबंध में क्रमश: 2011-12 और 2012-13 में केन्‍द्रीय हिस्‍से के रूप में 29.27 और 20.65 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई।

\*\*\*\*\*